जगत प्रकाश नड्डा
सांसद,
राष्ट्रीय महामंत्री

भारतीय जनता पार्टी
Bharatiya Janata Party

दिनाँक : 19 दिसम्बर, 2014

प्रिय बंधुवर/भगिनी,

नमस्कार!

प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में बनी एनडीए सरकार ने अपने कार्यकाल के 6 महीने पूरे किए हैं। इतनी कम अवधि में भी एनडीए सरकार ने कई मोर्चों पर अच्छी सफलता हासिल की है। इस सफल कार्यकाल के महत्वपूर्ण बिंदु जनता के सामने उजागर करने की दृष्टि से सभी प्रदेशों में महत्वपूर्ण स्थानों पर पत्रकार – वार्ताएं आयोजित करना तय हुआ है। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल जैसे प्रदेशों में चार प्रमुख स्थानों पर; बिहार, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम जैसे प्रदेशों में तीन और हरियाणा, पंजाब, जम्मू–कश्मीर, उत्तराखंड, तेलंगाना, केरल जैसे प्रदेशों में दो स्थानों पर पत्रकार वार्ता संपन्न करनी है। अन्य राज्यों तथा केंद्र प्रदेशों में न्यूनतम एक स्थान पर अच्छे तरीके से प्रेस वार्ता का आयोजन हो, यह अपेक्षित है। यह सभी प्रेस वार्ताएं **दिनांक 25 दिसंबर से 31 दिसंबर 2014** के बीच में आयोजित होनी है।

जिन प्रदेशों में हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उन प्रदेशों में केंद्रीय मंत्री महोदय द्वारा प्रेस वार्ता हो, यह आग्रह है। साथ ही राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेशों के पदाधिकारी इनके द्वारा विभिन्न स्थानों पर पत्रकार वार्ताओं को संबोधित की जाए।

इन प्रेस वार्ताओं में जारी करने हेतु प्रेस नोट का एक प्रारूप हम इस पत्र के साथ भेज रहे हैं। अपने–अपने प्रदेशों के प्रादेशिक भाषा में उसे अनुवादित करते हुए व्यापक स्तर पर उपयोग में लाएं।

प्रेस वार्ताओं की यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूरी गंभीरता से इन वार्ताओं का आयोजन हो यह कृपया सुनिश्चित करें।

शेष शुभ।

आपका

(जगत प्रकाश नड्डा)

11, अशोक रोड, नई दिल्ली–110 001, दूरभाष : 23005700 फैक्स : 23005787
11, Ashok Road, New Delhi-110 001, Phone : 23005700 Fax : 23005787

भारतीय जनता पार्टी

(केंद्रीय कार्यालय)

11 अशोक रोड़, नई दिल्ली- 110001

दिनांक 20.12.2014

<u>एनडीए सरकार के छ महीने पूर्ण होने के उपलक्ष्य मे, विभिन्न स्थानों पर प्रस्तावित प्रेस वार्ताओं मे जारी करने हेतु वक्तव्य का प्रारूप</u>

<u>व्यक्तव्य</u>

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार ने 26 नवंबर 2014 को छह महीने पूरे किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लोक सभा चुनाव से पहले जनता से जो वादे किए उन्हें पूरा करने को सरकार ने कई कदम उठाए हैं। छह महीने की अल्पावधि में ही राजग सरकार ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। सरकार के उपायों से न सिर्फ आम लोगों का जीवन आसान हुआ है बल्कि एक मजबूत भारत की आधारशिला रखी है। बीते छह महीने में सरकार की प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:-

<u>महंगाई पर लगाम लगाई</u>

सरकार ने मंहगाई पर अंकुश लगाने के लिये राजकोषीय और प्रशासनिक उपाय करते हुए **500 करोड़ रुपये का मूल्य स्थिरीकरण कोष (Price Stabilization Fund)** स्थापित किया। प्याज और आलू की आपूर्ति बढ़ाने को न्यूनतम निर्यात मूल्य बढ़ाया राज्यों को जमाखोरी और कालाबाजारी के मामलों को शीघ्र निपटाने को विशेष अदालतें बनाने को कहा। **परिणामस्वरूप** छह महीने के भीतर ही महंगाई में रिकार्ड गिरावट दर्ज हुई है। थोक महंगाई दर पांच साल के न्यूनतम स्तर पर है। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति **दिसम्बर** 2014 में घटकर मात्र **0.00** प्रतिशत रह गई है जबकि संप्रग शासन में अक्टूबर 2013 में यह 7.24 प्रतिशत और मई 2014 में 6.18 प्रतिशत थी। इसी तरह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति अक्टूबर 2014 में घटकर मात्र 5.52 प्रतिशत रह गई है जबकि कांग्रेस की संप्रग सरकार के शासन में अक्टूबर 2013 में यह 10.17 प्रतिशत और मई 2014 में 8.28 प्रतिशत थी। इसके साथ ही **पेट्रोल और डीजल भी सस्ते हुए**। एक जून 2014 को नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 71.45 रुपये थी जो राजग सरकार के सत्ता में आने के बाद हुई कटौती के कारण **16**

दिसम्बर, 2014 को 61.33 रुपये प्रति लीटर रह गई है। पेट्रोल की कीमत में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दर से कमी आई है। एक जून 2014 को नई दिल्ली में डीजल की कीमत प्रति लीटर 57.28 रुपये थी जो राजग सरकार बनने के बाद हुई कटौती से **16 दिसम्बर, 2014 को 50.51** रुपये प्रति लीटर रह गई है। डीजल की कीमत में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दर से कमी आई है।

रोजगार सृजन और उद्यमिता को उच्च प्राथमिकता

युवाओं के कौशल विकास के लिए अलग मंत्रालय बनाया। विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने को **मेक इन इंडिया** कार्यक्रम शुरु किया । **परिणामस्वरूप** मोदी सरकार के पहले छह महीने में उठाए गए कदमों से आगामी वर्षों में करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा।

भ्रष्टाचार खत्म करने पर जोर

सूचना प्रौद्योगिकी आधारित पारदर्शी तंत्र बनाकर भ्रष्टाचार खत्म करने की दिशा में ई-क्रांति परियोजना की शुरुआत जिस पर अगले कुछ वर्षों में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे। ई-क्रांति को अमल में लाने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरु।

विदेश में कालाधन वापस लाने को विशेष कार्यदल का गठित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 27 मई को कैबिनेट की पहली बैठक में ही विशेष जांच दल (Special Investigation Team) का गठन किया गया। इसके बाद वित्त मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय दल स्विटजरलैंड भेजा। विदेशी बैंकों में खाताधारक 427 लोगों की पहचान, 250 लोगों ने खाता होने की बात स्वीकार की ।

नीतिगत अपंगता (Policy Paralysis) को दूर किया

संप्रग कार्यकाल में बने मंत्रिसमूहों को खत्म किया। सचिवों के साथ प्रधानमंत्री ने सीधे संवाद स्थापित कर नौकरशाही को निर्णय लेने को प्रोत्साहित किया। **परिणामस्वरूप** केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में बेहतर समन्वय और निर्णय प्रक्रिया में तेजी।

टीम इंडिया के रूप में कार्य किया

राज्यों को साथ लेकर चलने के विचार को व्यवहार में उतारा। जम्मू कश्मीर में भीषण बाढ़ तथा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में चक्रवातीय तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं में केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया। विभिन्न

कार्यक्रमों को शुरु करने से पहले राज्यों से संवाद की परंपरा शुरु की। **परिणामस्वरूप** प्राकृतिक आपदा से प्रभावितों को समय पर राहत और बचाव मुहैया कराना संभव हुआ।

100 नए स्मार्ट शहर बसाने की प्रक्रिया शुरु

100 नये स्मार्ट शहरों के लिये आम बजट में 7060 करोड़ रुपये का आवंटन **किया**। **परिणामस्वरूप** विकसित किए जाने वाले 100 शहरों की पहचान की गई। कई शहरों में काम शुरु ।

2019 तक स्वच्छ भारत

सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान लांच किया, स्वच्छ भारत कोष की स्थापना की। **परिणामस्वरूप** स्वच्छता एक आन्दोलन बन गया है, अलग-अलग क्षेत्र के लोग इससे जुड़े हैं।

उच्च अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन किया

सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक 2014 संसद से पारित कराया। **इससे** न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी आएगी।

गांवों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर काम शुरु

सरकार ने प्रधानमंत्री सांसद आदर्श गांव योजना शुरु की **और** योजना के तहत संसद सदस्यों ने गांवों का चयन किया, साथ ही 'ररबन' योजना पर भी काम चल रहा है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याणकारी उपाय किए

सरकार ने जीवन प्रमाण योजना शुरु की, बचत योजनाओं में पड़ी दावारहित धनराशि का इस्तेमाल वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय मदद देने के लिए करने की घोषणा **की और परिणामस्वरूप** पेंशनभोगियों को अब हर साल नवंबर जीवित होने का सबूत देने के लिए सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी। वित्तीय मदद मिलने से उनका जीवन आसान होगा।

आर्थिक पुनरुत्थान, विकास दर बढ़ी

लंबित आर्थिक सुधारों को लागू करते हुए कई राजकोषीय कदम उठाए जिससे निवेश चक्र को पुन: चालू किया जा सके। रेल, रक्षा और निर्माण क्षेत्र में एफडीआई नियम उदार बनाए। **परिणामस्वरूप** सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप **विकास दर बढ़ी।** वित्त वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर बढ़कर 5.7 प्रतिशत हो

गयी है जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार के कार्यकाल में वित्त वर्ष 2013-14 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में यह 4.7 प्रतिशत और अंतिम तिमाही (जनवरी-मार्च) में 4.6 प्रतिशत थी। इसके साथ ही **औद्योगिक उत्पादन सूचकांक ने भी रफ्तार पकड़ी।** लगातार नकारात्मक वृद्धि दर्ज करने वाले औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में भी राजग सरकार की कोशिशों से अब वृद्धि होने लगी है। सितंबर 2014 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 2.5 प्रतिशत वृद्धि हुई।

मध्यम वर्ग व नव मध्यम वर्ग की आकांक्षाएं पूरी करने पर जोर

सरकार ने आयकर से छूट की सीमा दो लाख रुपये से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए ढाई लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये की। परिणामस्वरूप महंगाई घटने तथा आयकर में राहत मिलने से मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग अब अपने भविष्य के लिए निवेश कर सकता है।

कृषि को फायदेमंद बनाने के उपाय किए

सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं, एमएसपी बढ़ाया। **जिससे** डीजल के दाम घटने से कृषि लागत कम आएगी। सरकार ने जो उपाय किए हैं उनके दूरगामी फायदे होंगे।

अविरल और निर्मल गंगा के लिए भाजपा प्रतिबद्ध

सरकार ने गंगा के लिए अलग मंत्रालय बनाया, आम बजट में 2037 करोड़ रुपये की नमामि गंगे योजना घोषित की । **परिणामस्वरूप** गंगा को प्रदूषण मुक्त करने का कार्यक्रम शुरु, प्रदूषणकारी उद्योगों को मार्च 2015 तक सेंसर लगाने को कहा। गंगा में गंदगी गिरने पर पूर्णत: रोक सुनिश्चित होगी।

गाय व गौवंश का संरक्षण

सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरु **किया और** देशी गायों के संरक्षण के लिए 500 करोड़ रुपये की इस योजना के तहत कई कार्यक्रमों को मंजूरी दी गई।

कुछ अन्य ऐतिहासिक उपलब्धियां

प्रधानमंत्री जन धन योजना में खुले गरीबों के बैंक खाते: प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त 2014 को लालकिले की प्राचीर से इस योजना की घोषणा की और 28 अगस्त 2014 को इसे राष्ट्रीय स्तर पर लाँच कर दिया। 22 नवंबर 2014 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 7.73 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इसमें से 4.58 करोड़ बैंक खाते ग्रामीण क्षेत्र

में तथा 3.14 करोड़ बैंक खाते शहरी क्षेत्र में हैं। जनगणना 2011 के अनुसार देश में 40 प्रतिशत परिवारों के पास बैंक खाते नहीं थे।

'मेक इन इंडिया' की शुरुआत: प्रधानमंत्री ने 25 सितंबर 2014 को 'मेक इन इंडिया' अभियान लांच किया। इसे सफल बनाने के लिए रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर अधिक किया गया है। इसके अलावा कई अन्य क्षेत्रों में भी एफडीआई की राह आसान बनाई। इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मिलने का रास्ता तैयार होगा।

कूटनीतिक मोर्चे पर लहराया पचरम: विदेश नीति के मोर्चे पर भी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने परचम लहराया है। सीमा पर गोलीबारी के मुद्दे पर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया है। अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत से दुनियाभर में भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा हुआ है। इराक संकट के दौरान फंसे भारतीयों को सफलतापूर्वक सुरक्षित निकाला गया। पड़ोसी देशों के साथ सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रखने के लिए सार्क देशों के प्रमुखों को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया।

डब्लयूटीओ में किसानों और गरीबों के हितों की रक्षा: भारत ने जुलाई 2014 में डब्ल्यूटीओ के व्यापार सरलीकरण समझौते पर दस्तखत करने से इंकार कर दिया। भारत ने साफ कहा कि पहले खाद्य सुरक्षा और कृषि सब्सिडी के मुद्दे पर उसकी चिंताएं दूर होनी चाहिए। राजग सरकार के इस सख्त रुख की वजह से ही अमेरिका, भारत के नजरिये का समर्थन करने को मजबूर हुआ। डब्लयूटीओ वार्ताओं में भारत की यह बड़ी जीत है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम: कर्मचारियों और श्रमिकों की भलाई के लिए सरकार ने यह कार्यक्रम अक्टूबर 2014 में लांच किया। इसके साथ ही न्यूनतम पेंशन भी 1000 रुपये तय की। साथ ही पीएफ के लिए यूनिवर्सल नंबर का शुभारंभ जिसकी मदद से कर्मचारी अपने पीएफ खाते को कहीं से भी संचालित कर सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास पड़े दावारहित 27,000 करोड़ रुपयों को श्रमिकों के हितों के लिए खर्च किया जाएगा।

सरकारी कार्यशैली में व्यापक बदलाव: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकारी कार्यशैली में व्यापक परिवर्तन आया है। सरकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज हुई है। संप्रग सरकार के कार्यकाल में सरकार में नीतिगत फैसले लेने की प्रक्रिया बिल्कुल ठप पड़ गई थी। इस संबंध में सबसे अहम फैसला संप्रग शासन में बने मंत्रि-समूहों को खत्म करके लिया गया है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों की हाजिरी के लिए http://attendance.gov.in/ शुरु की ताकि केंद्र के सभी कर्मचारी समय पर दफ्तर पहुंचें।

रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाई, रक्षा खरीद प्रक्रिया को गति दी: लंबित आर्थिक सुधारों को लागू करते हुए सरकार ने रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 26 प्रतिशत से

बढ़ाकर 49 प्रतिशत की। फिलहाल भारत 70 प्रतिशत रक्षा सामान आयात करता है। इस फैसले से देश में ही रक्षा उपकरणों की मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सकेगा। सरकार ने एक फैसले में ही 80,000 करोड़ रुपये की रक्षा खरीद को मंजूरी दी। यूपीए सरकार ने रक्षा खरीद पर कोई फैसला न करके देश की सुरक्षा से समझौता किया था। रक्षा क्षेत्र के साथ-साथ रेल और निर्माण क्षेत्र में भी एफडीआई की सीमा बढ़ाई गई।

<u>24 घंटे बिजली:</u> चौबीस घंटे बिजली देने का वादा पूरा करने के लिए मोदी सरकार ने 43,000 करोड़ रुपये की दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को मंजूरी दी है। इसके अलावा बिजली क्षेत्र में कई व्यापक सुधार भी किए हैं।

इस तरह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार ने **'सबका साथ, सबका विकास'** नीति पर अमल करते हुए छह महीने से भी कम समय में **'एक भारत, श्रेष्ठ भारत'** के निर्माण की ठोस शुरुआत की है। आने वाले दिनों में ऐसे ही कई लोक कल्याणकारी उपाय देखने को मिलेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी और उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है।

दूसरी ओर हताश कांग्रेस पार्टी के नेता आजकल अनर्गल राग अलाप रहे हैं। वे राजग सरकार से छह महीने का हिसाब मांग रहे हैं। जिस पार्टी ने 60 साल तक शासन कर देश को तरक्की से वंचित रखा, करोड़ों लोगों को गरीबी में जीने को मजबूर किया, युवाओं के हाथों में बेरोजगारी की हथकड़ियां डाले रखीं, जिसने लोकतंत्र का गला घोंटने की कोशिश की, वही पार्टी आज छह महीने के शासन का हिसाब मांग रही है। ऐसी शोषणकारी, दमनकारी, अलोकतांत्रिक पार्टी को भाजपा के छह माह के शासन का हिसाब मांगने का कोई हक नहीं है। कांग्रेस पार्टी को उसके 60 साल के कुशासन और भ्रष्टाचार की सजा देश की जनता 2014 के लोकसभा चुनाव में और उसके बाद हरियाणा व महाराष्ट्र विधान सभा के चुनाव में दे चुकी है। अब झारखंड और जम्मू कश्मीर की जनता भी कांग्रेस को करारी मात देने को तैयार है। ऐसे में निराशा में डूबे कांग्रेस के नेताओं की मनोदशा को सहज ही समझा जा सकता है। इसी हताशा के चलते कांग्रेस को राजग सरकार की उपलिब्धयां नजर नहीं आ रहीं।

बहरहाल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी टीम ने मात्र छह महीने में ही असाधारण उपलब्धियां अर्जित की हैं। सरकार जब 60 महीने का अपना रिपोर्ट कार्ड जनता की अदालत में रखेगी तब निश्चित ही उपलब्धियों की फेहरिस्त और लंबी होगी।

(इंजी अरूण कुमार जैन)
कार्यालय सचिव